

माननीय श्री जी.सी.मितल और के.पी.भंडारी न्यायमूर्ति केसमक्ष

डॉ लाल सांगा,-अपीलकर्ता।

बनाम

स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा संस्थान और अनुसंधान, चंडीगढ़ और अन्य, -प्रतिवादी।

पत्र पेटेंट अपील संख्या 198,9 का 2104।

30 अगस्त, 1990.

भारत का संविधान, 1950-कला. 14 और 226-स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश-अपीलकर्ता प्रवेश के लिए पात्र-मामूली छिपाव- प्रवेश पत्र में उल्लेख - अनजाने में हुई गलती जिसका प्रवेश पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है - उम्मीदवार की अयोग्यता - प्रवेशित छात्र की वैधता - क्या अयोग्य ठहराया जा सकता है।

माना गया कि इस गलती का उसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न ही यह गलती अपीलकर्ता की ओर से नैतिक मानक में कोई कमी दर्शाती है। हमारी राय में, पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार जो निदेशक को किसी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार देता है, जानकारी को छिपाना ऐसा होना चाहिए जो जानबूझकर किया गया हो और जिसका उम्मीदवार के प्रवेश की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। के मामले में कहा पाठ्यक्रम! मेरिट सूची की तैयारी. इस मामले में, अपीलकर्ता ने अपनी योग्यता, अनुभव या पात्रता के संबंध में कोई गलत जानकारी नहीं दी। उन्हें योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था।

(पैरा 6)

माना गया कि वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दी गई सजा अत्यधिक मनमानी, कठोर और अनुपातहीन है। संस्थान के निदेशक, जो खुद एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, को अपीलकर्ता, जो खुद भी एक डॉक्टर है, के मामले का इलाज करने में अधिक उदार होना चाहिए था, क्योंकि उनकी गलती, यदि कोई थी, इतनी गंभीर नहीं थी कि सभी को नुकसान पहुंचे। उसका कैरियर। इस कारण से भी, हमारी राय है कि अपीलकर्ता पर उपरोक्त दंड

लगाने का निदेशक का आदेश बरकरार नहीं रखा जा सकता है। इसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन मानते हुए रद्द किया जाना चाहिए।

(पैरा 10)

माना गया कि पुस्तिका में शामिल प्रावधान केवल संस्थान के निदेशक को किसी छात्र को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार देते हैं या वह कोई अन्य उचित कार्रवाई कर सकते हैं। इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रवेश के समय ही करने का इरादा था। एक बार जब कोई उम्मीदवार संस्थान में लगभग तीन वर्षों तक अध्ययन कर चुका होता है और उसके पाठ्यक्रम में भाग ले चुका होता है, तो निदेशक, अपने कार्य को उचित ठहराने के लिए पुस्तिका में निहित प्रावधानों की मदद नहीं ले सकता है। यह प्रतिवादी का कर्तव्य था कि वह प्रासंगिक समय पर मामले को यथासंभव गहनता से स्वीकार करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाए। यदि उन्होंने किसी अभ्यर्थी को दाखिला दे दिया है और उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी है, तो उन्हें संस्थान के रोल से उसका नाम हटाने और उसे परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित करने और संस्थान के निवासियों के भविष्य के किसी भी चयन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित करने से रोका जाता है। .

(पैरा 7)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—याचिकाकर्ता का नाम रोल से हटा दिया गया और परीक्षाओं में बैठने से अयोग्य घोषित कर दिया गया—दंड लगाने का अधिकार एक विधायी कार्य है—प्रशासनिक निर्देशों के तहत सजा—संस्थान वैधानिक नियम नहीं बना रहा—वैधानिक नियमों के अभाव में सजा—क्या कानूनी रूप से टिकाऊ है .

माना गया कि केवल कार्यकारी निर्देश से किसी उम्मीदवार को कोई सजा नहीं दी जा सकती। किसी अभ्यर्थी का नाम संस्थान के रोल से हटाना या उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित करना या संस्थान में किसी भी भविष्य के चयन के लिए अयोग्य घोषित करना गंभीर दंड है। इस तरह की सजा देने से पहले, निदेशक को कुछ कानून द्वारा शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और किसी उम्मीदवार को सजा देने से पहले कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।

(पैरा 12)

यह माना गया कि जुर्माना लगाने का निर्धारण करने की शक्ति अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है। या तो विधायिका स्वयं किसी कार्य या चूक के लिए दंड निर्धारित कर

सकती है या यह कानून द्वारा नियमों और विनियमों द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को किए जाने वाले कार्यों को सौंप सकती है। किसी नागरिक को किसी कार्य या चूक के लिए दंडित करने से पहले दंड निर्धारित करने की विधायी मंजूरी एक शर्त है। यही कारण है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों ने छात्रों पर क्या दंड लगाया जाना है और ऐसे दंड देने से पहले किस प्रक्रिया का पालन किया जाना है, इसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यादेश बनाए हैं। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा कोई वैधानिक नियम हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। केवल पुस्तिका में दिए गए कार्यकारी निर्देशों के आधार पर, अपीलकर्ता को दंड देने का उत्तरदाताओं के पास कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से भी प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता पर विभिन्न दंड लगाने के आक्षेपित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि उक्त आदेश किसी कानूनी प्राधिकरण द्वारा समर्थित नहीं है।

(पैरा 14)

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226—कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद छात्र को अयोग्य घोषित करना—कोई पूछताछ नहीं—प्राकृतिक न्याय के हित में उल्लंघन करने पर उसे दंडित किया जाएगा।

माना गया कि वर्तमान मामले में निदेशक ने केवल अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, उन्होंने आवेदन में लगाए गए आरोपों की कोई जांच नहीं की। वर्तमान प्रकार के मामले में, प्राकृतिक न्याय के हित में, अपीलकर्ता को सजा देने से पहले जांच करना संस्थान के निदेशक के लिए अनिवार्य था। (पैरा 15)

लेटर्स पेटेंट दिनांक 26 मई, 1989 के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड एक्स के तहत अपील। माननीय श्री न्यायमूर्ति जे.वी. गुप्ता द्वारा सी.डब्ल्यू.जे. में पारित। 1987 का क्रमांक 7933.

अपीलकर्ताओं की ओर से के.एस. सैनी, अधिवक्ता और सुश्री अंजू सैनी, अधिवक्ता।

प्रतिवादियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डी. एस. नेहरा और अरुण नेहरा, अधिवक्ता।

निर्णय

आदेश के.बी. भंडारी, न्यायमूर्ति:

1. यह 1987 की सिविल रिट याचिका संख्या 7933 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 26-5-1989 के खिलाफ एक लेटर्स पेटेंट अपील है। संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं:--

अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। एम.बी.बी.एस. पास करने के बाद। वर्ष 1980 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल मेडिकल कॉलेज, इम्फाल (मणिपुर) से परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उन्हें उपरोक्त कॉलेज में बायो-कैमिस्ट्री में डिमॉन्स्ट्रेटर के रूप में नियुक्त किया गया। अपीलकर्ता ने सर्जरी, स्त्री रोग, पैथोलॉजी विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (बाद में इसे 'पी.जी.आई.ए. चंडीगढ़ में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। आदि। जुलाई, 1984 से शुरू होने वाले सत्र के लिए अपने आवेदन दिनांक 28-3-1984 के माध्यम से। आवेदन पत्र में कॉलम 13 (सी) में अनुभव, यदि कोई हो, से संबंधित, अपीलकर्ता ने कहा कि वह बायो-केमिस्ट के पद पर था। आर. एम. कॉलेज और अस्पताल, इम्फाल में, रु. 700/- प्रति माह और जून 1982 से जून 1983 की अवधि के लिए भते। उक्त आवेदन के कॉलम 18 के सामने जहां उन्हें उस तारीख को सूचित करने की आवश्यकता थी, जब से वह सरकारी / अर्ध-सरकारी संस्थान / अस्पताल में कार्यरत थे, यदि वह थे सेवा में, अपीलकर्ता ने 'शून्य' का उल्लेख किया। स्नातकोत्तर एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के संबंध में सूचना पुस्तिका में निम्नलिखित चेतावनी अंकित की गई थी:--

"यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा पाया जाता है गलत जानकारी या प्रमाण पत्र आदि प्रदान किया या अपने आवेदन पत्र में कुछ जानकारी छिपाई या छिपाई हुई पाई गई, तो उसे प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। संस्थान के निदेशक द्वारा उचित समझी जाने वाली कोई अन्य कार्रवाई भी उसके विरुद्ध की जा सकती है।"

प्रिंसिपल, रीजनल मेडिकल कॉलेज, मणिपुर के दिनांक 27-4-1987 के पत्र से यह पी.जी.आई. के संज्ञान में आया। कि डॉ. लाल सांगा ने संस्थान से कुछ जानकारी छुपायी थी। उक्त पत्र अनुबंध आर-1 के आधार पर, अपीलकर्ता को 3-6-1987 को एक कारण बताओ नोटिस अनुबंध आर-2 जारी किया गया था, जिसमें उसे स्थिति स्पष्ट करने की आवश्यकता थी। उन्होंने 12-6-1987 को अपना उत्तर अनुलग्नक पी-4 प्रस्तुत किया। इसमें उन्होंने बताया कि वह इम्फाल के रीजनल मेडिकल कॉलेज में बायो-कैमिस्ट्री में

डिमाँन्स्ट्रेटर के पद पर कार्यरत थे, लेकिन उनकी रुचि सर्जरी में थी, इसलिए वह सर्जरी में आगे की पढ़ाई करना चाहते थे। ऐसा करने के लिए, उन्होंने बिना वेतन के असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया और किसी ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई। अपीलकर्ता के अनुसार, उन्होंने सोचा कि बिना वेतन और बिना किसी प्रायोजन के असाधारण छुट्टी एक खुली आरक्षित श्रेणी के रूप में उनकी उम्मीदवारी को योग्य बना सकती है। उनके अनुसार, जब उन्होंने वर्तमान फॉर्म भरा तो उन्हें इसके महत्व और निहितार्थ का एहसास नहीं था। उन्होंने जवाब में आगे कहा, 'सर, अब जब मैं सर्जरी में अपनी तीन साल की रेजीडेंसी पूरी कर रहा हूँ तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मेरी अपनी पिछली नौकरी को जारी रखने की कोई इच्छा नहीं है और न ही मेरा कोई भविष्य है और मैंने अपने इस्तीफे के लिए आवश्यक कदम उठा लिए हैं। इसलिए, मैं आपसे और आपके अच्छे कार्यालयों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया मेरी स्थिति और भविष्य के करियर पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और मुझ पर दया करें और मेरी अज्ञानता को क्षमा करें।

2. उपरोक्त स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद संस्थान के निदेशक द्वारा आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-5 पारित किया गया। अपीलकर्ता ने फिर से अनुबंध पी-6 के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उसने प्रस्तुत किया कि उसने अपने राज्य से प्रायोजन के लिए प्रयास किया लेकिन उसे नहीं मिला और फिर जूनियर रेजीडेंसी के लिए आवेदन पत्र दाखिल करने से पहले, उसने असाधारण छुट्टी के लिए आवेदन किया, जिसकी उसे शायद ही उम्मीद थी और इसलिए, उन्होंने आवेदन में उल्लेख किया कि यदि छुट्टी नहीं थी आवश्यक अवधि के लिए दी गई अनुमति को त्यागपत्र माना जा सकता है। अपीलकर्ता ने इस संबंध में मणिपुर सरकार के मुख्यमंत्री के एक पत्र, प्रति संलग्नक पी-8 पर भी भरोसा किया। इस मामले पर संस्थान के निदेशक द्वारा फिर से विचार किया गया। हालाँकि, संस्थान के निदेशक ने इस मामले में कुछ भी करने पर खेद जताया। इसके बाद, अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। 1987 की उक्त रिट याचिका संख्या 7933 विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष आई, जिन्होंने पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद इसे खारिज कर दिया।

3. जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, अपीलकर्ता अनुसूचित जनजाति का सदस्य है। उन्हें अनुसूचित जनजाति के सदस्य के रूप में संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश मिला। आवेदन करने की उनकी पात्रता के बारे में कोई विवाद नहीं है और उन्हें उनकी योग्यता के आधार पर प्रवेश की अनुमति दी गई थी। उन्होंने संस्थान में तीन साल तक

व्यावहारिक रूप से अध्ययन किया। मोशन बेंच के आदेश के तहत उन्हें परीक्षा में शामिल होने की इजाजत भी दे दी गयी।

4. के आदेश का ऑपरेटिव भाग. संस्थान के निदेशक दिनांक 12-6-1987 इस प्रकार पढ़ते हैं:--

"i) डॉ. लाल सांगा का नाम तत्काल प्रभाव से संस्थान की सूची से हटा दिया गया है।

ii) डॉ. लाल सांगा एम.एस. में उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे। (सर्जरी) परीक्षा भविष्य में संस्थान द्वारा आयोजित की जाएगी।

iii) डॉ. लाल सांगा को इस संस्थान के निवासियों के भविष्य के किसी भी चयन में शामिल होने के लिए अयोग्य ठहराया गया है।

5. पोस्ट ग्रेजुएट और पोस्टडॉक्टरल पाठ्यक्रमों के संबंध में जानकारी की पुस्तिका में शामिल प्रावधानों का उद्देश्य निदेशक को आवेदन पत्र में तथ्यों के किसी भी अनजाने गलत विवरण के लिए संस्थान के रोल से किसी उम्मीदवार का नाम हटाने का अधिकार देना नहीं है। प्रावधानों का उद्देश्य उस उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करना है जो उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता पूरी नहीं करता है। अपीलकर्ता को योग्यता के आधार पर उसकी योग्यता के आधार पर भर्ती किया गया था। उन्होंने कानूनी की सराहना नहीं की असाधारण छुट्टी की मंजूरी के लिए आवेदन पत्र भरते समय निहितार्थ और जिसमें उन्होंने अधिकारियों से अनुरोध किया कि यदि असाधारण छुट्टी नहीं दी गई है, तो इसे उनका इस्तीफा माना जाए। उन्होंने उस आवेदन को सेवा से अपना त्यागपत्र मान लिया। अपीलकर्ता को इस अनजाने में हुई गलती के कारण कोई मौद्रिक लाभ नहीं मिला। उनका इस्तीफा दिनांक 14-7-1987 से प्रभावी आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। 1-3-1984. इस संबंध में, कार्यवाहक सचिव, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज सोसायटी, मणिपुर द्वारा पारित आदेश इस प्रकार है:--

"केंद्रीय सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 के नियम 5 के उप-नियम (1) के परंतुक के अनुसरण में, माननीय अध्यक्ष, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय मेडिकल कॉलेज सोसायटी, मणिपुर, को बर्खास्त करने की कृपा है डॉ. लाल सांगा, प्रदर्शक जैव रसायन विभाग की सेवा दिनांक 01.11.2017 से। 1-3-1984 और निर्देश दिया कि वह अपनी सेवाओं की समाप्ति से ठीक पहले 1 (एक) महीने के लिए उसी दर पर वेतन और भत्ते का दावा करने का हकदार होगा जिस दर पर वह प्राप्त कर रहा था।

इस आदेश से स्पष्ट है कि अपीलार्थी का त्यागपत्र दिनांक 1-3-1984 से स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रकार, इस आदेश के अनुसार, आवेदन की तिथि पर, अपीलकर्ता सरकार की सेवा में नहीं रहा। इस अनजाने में हुई गलती के लिए एम.डी. पाठ्यक्रम के छात्र अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कठोर कार्रवाई की सराहना करना बहुत मुश्किल है। इस गलती का उसके स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। न ही यह गलती अपीलकर्ता की ओर से नैतिक मानक में कोई कमी दर्शाती है। हमारी राय में, पुस्तिका में निहित प्रावधानों के अनुसार जो निदेशक को किसी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करने का अधिकार देता है, जानकारी को छिपाना ऐसा होना चाहिए जो जानबूझकर किया गया हो और जिसका उम्मीदवार के प्रवेश की संभावनाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। कहा कि पाठ्यक्रमों की मेरिट सूची तैयार करने के संबंध में। यहां इस मामले में, जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, अपीलकर्ता ने अपनी योग्यता, अनुभव या पात्रता के संबंध में कोई गलत जानकारी नहीं दी है। उन्हें योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था। इस संबंध में प्रश्न कि क्या वह किसी विशेष पद पर कार्यरत था तारीख ऐसी प्रकृति की नहीं है जिस पर पुस्तिका में दिए गए दंडात्मक प्रावधान लागू हों। हमारी राय में, अपीलकर्ता के खिलाफ सजा पारित करने में प्रतिवादी की कार्रवाई पुस्तिका में निहित प्रावधानों के दायरे से बाहर नहीं है जो संस्थान के निदेशक को एक उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करने में सक्षम बनाती है।

6. मामले का एक और पहलू भी है। पुस्तिका में शामिल प्रावधान केवल संस्थान के निदेशक को किसी छात्र को प्रवेश से वंचित करने या कोई अन्य उचित कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं। इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रवेश के समय ही करने का इरादा है। एक बार जब एक उम्मीदवार ने संस्थान में लगभग तीन वर्षों तक अध्ययन किया है और उसके पाठ्यक्रम में भाग लिया है, तो निदेशक, अपने कार्य को सही ठहराने के लिए बुक-लेट में निहित प्रावधानों की मदद नहीं ले सकता है: यह उत्तरदाताओं का कर्तव्य था कि वे मामले पर कार्रवाई करें। प्रासंगिक समय पर यथासंभव पूर्ण रूप से प्रवेश। यदि उन्होंने किसी अभ्यर्थी को दाखिला दे दिया है और उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे दी है, तो उन्हें संस्थान के रोल से उसका नाम हटाने और उसे परीक्षा में बैठने से अयोग्य घोषित करने और संस्थान के निवासियों के भविष्य के किसी भी चयन में उपस्थित होने से अयोग्य घोषित करने से रोका जाता है। .

7. यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पुस्तिका के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक को संस्थान के रोल से किसी उम्मीदवार का नाम हटाने और यह घोषित करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है कि कोई उम्मीदवार ऐसा करेगा। परीक्षा में बैठने के लिए पात्र नहीं

होगा और आगे चलकर उसे प्रतिवादी-संस्थान के किसी भी भविष्य के चयन से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। पुस्तिका के प्रावधानों से ऐसी किसी शक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। पुस्तिका में प्रावधान किसी अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम में प्रवेश से वंचित करने तक सीमित है। इसलिए, हमारी राय में, उचित रूप से व्याख्या करने पर, निदेशक का आदेश पुस्तिका में निहित प्रावधानों के दायरे से बाहर है। यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि पुस्तिका में, जो किसी उम्मीदवार को प्रवेश से वंचित करने का प्रावधान करती है, संस्थान के निदेशक के मार्गदर्शन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। यह संस्थानकला के उद्देश्य से राज्य का एक साधन है। भारतीय संविधान के 12. हमारे पास है संस्थान के निदेशक द्वारा अपीलकर्ता के खिलाफ पारित सजा के आदेश पर हमने उत्सुकतापूर्वक विचार किया। अपीलकर्ता की ओर से एक बहुत ही छोटी सी चूक के लिए, निदेशक ने एक सजा दी है जो बहुत कठोर, अनुचित और अनुपातहीन है।

8. शंकर दास बनाम भारत संघ, AIR 1985 SC 772 : 1985 Lab IC 590 में, एक सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया था रुपये की एक छोटी राशि के गबन के लिए सेवा. 500/-. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के आलोक में प्रश्न पर विचार करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि दी गई सजा मनमानी, अनुचित और अनुपातहीन है और खारिज कर दी गई सेवा से हटाने का आदेश.

9. सर्वोच्च न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णय के अनुपात को लागू करते हुए, हमारी राय में, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को दी गई सजा अत्यधिक मनमानी, कठोर और अनुपातहीन है। संस्थान के निदेशक, जो खुद एक प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं, को अपीलकर्ता, जो खुद भी एक डॉक्टर है, के मामले का इलाज करने में अधिक उदार होना चाहिए था, क्योंकि उनकी गलती, यदि कोई थी, इतनी गंभीर नहीं थी कि सभी को नुकसान पहुंचे। उसका कैरियर। इस कारण से भी, हमारी राय है कि अपीलकर्ता पर उपरोक्त सजा लगाने के निदेशक के आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसे कला का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया जाना चाहिए। संविधान के 14.

10. पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। इसे एक विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। यह संसद के अधिनियम संख्या 51 के तहत अस्तित्व में आया जिसे पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़, अधिनियम, 1966 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के रूप में जाना जाता है। 'अधिनियम' की धारा 31 के अनुसार; केंद्र सरकार को, संस्थान के परामर्श के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए नियम बनाने का अधिकार है। नियम बनाने की शक्ति

संस्थान निकाय को प्रदान की गई है, जिसका प्रयोग केंद्र सरकार की मंजूरी से किया जाएगा। इस संबंध में अधिनियम की धारा 32 के प्रावधानों को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है:--

"32. विनियम बनाने की शक्ति :-- (1) संस्थान, केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए और इसकी व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम बना सकता है। शक्ति, ऐसे नियम प्रदान कर सकते हैं-

(ए) संस्थान की पहली बैठक के अलावा अन्य बैठकों को बुलाना और आयोजित करना, वह समय और स्थान जहां ऐसी बैठकें आयोजित की जानी हैं, ऐसी बैठकों में कामकाज का संचालन और कोरम बनाने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या;

(बी) शासी निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के गठन का तरीका, कार्यालय की अवधि, और शासी निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के सदस्यों के बीच रिक्तियों को भरने का तरीका;

(सी) संस्थान के अध्यक्ष और शासी निकाय के अध्यक्ष द्वारा प्रयोग और निर्वहन की जाने वाली शक्तियां और कार्य;

(डी) शासी निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों को भुगतान किए जाने वाले भत्ते, यदि कोई हों।

(ई) शासी निकाय और स्थायी और तदर्थ समितियों द्वारा उनके व्यवसाय के संचालन, उनकी शक्तियों के प्रयोग और उनके कार्यों के निर्वहन में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) संस्थान द्वारा नियुक्त शिक्षकों सहित संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के पद का कार्यकाल, वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

(छ) शासी निकाय के अध्यक्ष की शक्तियां और कर्तव्य;

(ज) संस्थान के निदेशक और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।

(i) की संपत्तियों का प्रबंधन संस्थान.

(जे) डिग्री, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं और उपाधियां जो संस्थान द्वारा प्रदान की जा सकती हैं;

(के) प्रोफेसरशिप, रीडरशिप, लेक्चरशिप और अन्य पद जो स्थापित किए जा सकते हैं और ऐसे व्यक्ति जिन्हें ऐसी प्रोफेसरशिप, रीडरशिप, लेक्चरशिप और अन्य पदों पर नियुक्त किया जा सकता है;

(एल) फीस और अन्य शुल्क जो संस्थान द्वारा मांगे और प्राप्त किए जा सकते हैं;

(एम) संस्थान के अधिकारियों, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए पेंशन और भविष्य निधि का गठन किस तरीके से और किन शर्तों के अधीन किया जा सकता है;

(एन) कोई अन्य मामला जिसके लिए इस अधिनियम के तहत विनियमों द्वारा प्रावधान किए जा सकते हैं।"

(2) xx xx xx xx"

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, खंड 32(जे) संस्थान की डिग्री, डिप्लोमा और अन्य विशिष्टताएं आदि प्रदान करने की शक्तियों से संबंधित है, जबकि खंड 32(के) संस्थान के शासी निकाय को विभिन्न पद और नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों को बनाने का अधिकार देता है। ऐसी पोस्टों को.

11. संस्थान निकाय को संस्थान में विभिन्न पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों के प्रवेश को सुव्यवस्थित करने के लिए वैधानिक नियम बनाने का अधिकार है। यह उसके द्वारा किए गए किसी भी कदाचार के लिए छात्रों को अयोग्य ठहराने या निष्कासन का प्रावधान कर सकता है। हमने उत्तरदाताओं के विद्वान वकील, श्री डी.एस. नेहरा, को यह जानकारी देने के लिए बुलाया कि क्या संस्थान निकाय द्वारा नियम बनाने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए स्नातकोत्तर और पोस्टडॉक्टोरल पाठ्यक्रमों के बारे में जानकारी की पुस्तिका जारी की गई है। उन्होंने बार में बयान दिया है कि पी.जी.आई. ने छात्रों को दी जाने वाली सजा से निपटने के लिए कोई वैधानिक नियम नहीं बनाए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुस्तिका को विनियम का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए, इसे संस्थान निकाय द्वारा बनाया गया विनियमन नहीं माना जा सकता है। प्रत्येक "विश्वविद्यालय परीक्षाओं में बैठने से अयोग्यता का दंड लगाने या विश्वविद्यालय से निष्कासन को विनियमित करने के लिए वैधानिक अध्यादेश बनाता है। विश्वविद्यालय की स्थायी समिति द्वारा ऐसे मामलों पर विचार करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। स्थायी

समिति उचित जांच करती है और उम्मीदवारों को बचाव का पूरा मौका देती है। उदाहरण के लिए, पंजाब विश्वविद्यालय कैलेंडर खंड II 1984 अध्याय 2 में किसी उम्मीदवार पर कोई भी दंड लगाने के लिए इतनी विस्तृत प्रक्रिया शामिल है। केवल कार्यकारी निर्देश से किसी उम्मीदवार को कोई सजा नहीं दी जा सकती। किसी अभ्यर्थी का नाम संस्थान के रोल से हटाना या उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित करना या संस्थान में किसी भी भविष्य के चयन के लिए अयोग्य घोषित करना गंभीर दंड है। इस तरह की सजा देने से पहले, कुछ सॉ द्वारा निदेशक को शक्ति प्रदान की जानी चाहिए और किसी उम्मीदवार को सजा देने से पहले कानून द्वारा एक प्रक्रिया निर्धारित की जानी चाहिए।

12. यू.एस. बनाम ईटन (1892) 144 यूएस 677 में यह निर्धारित किया गया है कि किसी कार्य को आपराधिक अपराध बनाने की शक्ति अनिवार्य रूप से विधायी शक्ति का एक प्रयोग है जिसे प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है। प्रशासनिक नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए कोई भी दंड विधानमंडल द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। **सेठिया प्रॉपर्टीज़ बनाम भवनानी** (1960) 64 सी.डब्ल्यू.एन. 899 (930) में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि विधानमंडल नियम बनाने की शक्ति सौंप सकता है और नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करे। लेकिन सटीक दंड निर्धारित करने के बजाय, यह सीमा या मानक निर्धारित कर सकता है, और प्रशासनिक निकाय पर छोड़ सकता है कि वह ऐसी सीमाओं के भीतर या निर्धारित मानक के अनुसार दंड निर्धारित करे।

13. उपरोक्त चर्चा से, यह स्पष्ट है कि जुर्माना लगाने की शक्ति अनिवार्य रूप से एक विधायी कार्य है। या तो विधायिका स्वयं किसी कार्य या चूक के लिए दंड निर्धारित कर सकती है या यह कानून द्वारा नियमों और विनियमों द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी को किए जाने वाले कार्यों को सौंप सकती है। किसी नागरिक को किसी कार्य या चूक के लिए दंडित करने से पहले दंड निर्धारित करने की विधायी मंजूरी एक शर्त है। यही कारण है कि देश के सभी विश्वविद्यालयों ने दंड देने की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अध्यादेश बनाये हैं। छात्रों पर लगाए जाने वाले दंड और ऐसे दंड देने से पहले अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। लेकिन वर्तमान मामले में ऐसा कोई वैधानिक नियम नहीं है हमारे संज्ञान में लाया गया है. केवल पुस्तिका में निहित कार्यकारी निर्देशों की ताकत के कारण, उत्तरदाताओं पर अपीलकर्ता पर लागू दंड लगाने का कोई अधिकार नहीं है। इस कारण से भी अपीलकर्ता पर विभिन्न दंड लगाने वाले उत्तरदाताओं के विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता क्योंकि उक्त आदेश किसी कानूनी प्राधिकारी द्वारा समर्थित नहीं है।

14. वर्तमान मामले में निदेशक ने केवल अपीलकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया। उन्होंने आवेदन में लगाए गए आरोपों की कोई जांच नहीं की। वर्तमान प्रकार के

मामले में, प्राकृतिक न्याय के हित में, अपीलकर्ता को सजा देने से पहले जांच करना संस्थान के निदेशक के लिए अनिवार्य था। किसी भी मामले में, निदेशक को कार्यवाहक सचिव से दिनांक 14-7-1987 का आदेश प्राप्त होने के बाद, 1-3-1984 से अपीलकर्ता का इस्तीफा स्वीकार करते हुए, उत्तरदाताओं की ओर से मामले पर पुनर्विचार करना और विचार करना अनिवार्य था। मामले की उचित जांच हो. एक बार अपीलकर्ता का इस्तीफा दिनांक 01.10.19 से स्वीकार कर लिया जाता है। 1-3-1984, इसका मतलब यह है कि जिस दिन उन्हें उत्तरदाताओं द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश दिया गया था, वह सरकार की सेवा में नहीं थे। इस कारण भी प्रतिवादियों का अपीलकर्ता पर उपरोक्त दंड लगाने का आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए अवैध है।

15. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर हम प्रतिवादियों द्वारा अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को बरकरार रखने में विद्वान एकल न्यायाधीश से सहमत होने में असमर्थ हैं। तदनुसार, यह अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया जाता है। सर्टिओरारी की एक रिट जारी की जाती है, जिससे प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा पारित आदेश अनुलग्नक पी -5 को रद्द कर दिया जाता है। उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता के परिणाम को तुरंत घोषित करने का निर्देश दिया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

16. अपील की अनुमति.

अस्वीकरण स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
जिला न्यायालय, गुरुग्राम, हरियाणा